



उत्तर प्रदेश में सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. वीरेन्द्र प्रताप चौरसिया

असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), राजकीय डिग्री कॉलेज कालपी, जालौन, उत्तर प्रदेश।

(Corresponding Author: virendrauphd@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21790001>

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तर प्रदेश के राज्य सहयोगी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) के वित्तीय स्वास्थ्य और परिचालन दक्षता का अध्ययन किया गया है। शोध पत्र मुख्य रूप से सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के वित्तीय संकेतकों जैसे—एनपीए अनुपात, वसूली दर, लाभप्रदता और बाजार हिस्सेदारी का मुख्य रूप से अध्ययन करता है। इस अध्ययन में वर्ष 2010 से 2025 तक के द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, जिनका संकलन इंडियास्टैट से किया गया है जो मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), नाबार्ड और नाफ्सकोब के आँकड़ों पर आधारित है। आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि, उत्तर प्रदेश के एससीएआरडीबी में वर्ष 2024 में एनपीए का स्तर 76.2 प्रतिशत है, जो चिंताजनक स्थिति का परिचायक है, जबकि इसी दौरान वसूली दर मात्र 27.7 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इसके अतिरिक्त, कृषि ऋण प्रवाह में सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय हिस्सेदारी जो 2012 में 18 प्रतिशत थी वह कम होकर 2025 में 9 प्रतिशत के स्तर पर आ गई है, जो वाणिज्यिक बैंकों के बढ़ते वर्चस्व और सहकारी संस्थाओं के श्रंखनात्मक हाशिष्ट की स्थिति को दर्शाती है। शोध से प्राप्त निष्कर्ष में एक विरोधाभास भी देखने को मिलता, जहाँ उत्तर प्रदेश का अल्पकालिक सहकारी ढांचा (राज्य सहकारी बैंक एसटीसीबी एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक डीसीसीबी) लाभप्रदता और निम्न एनपीए के साथ सुदृढ़ हो रहा है, वहीं दीर्घकालिक ऋण संरचना (एससीएआरडीबी) अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, यह शोध पत्र सुझाव देता है कि दीर्घकालिक सहकारी बैंकों को पुनर्जीवित करने के लिए कठोर वसूली तंत्र, व्यावसायिक प्रबंधन और तकनीकी एकीकरण की आवश्यकता है। बिना इन सुधारों के, ग्रामीण उत्तर प्रदेश में पूंजी निर्माण और कृषि विविधीकरण सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी।

आलेख संख्या	प्राप्त: 06 मई, 2026	स्वीकृत: 25 मई, 2026	प्रकाशित: 30 जून, 2026
	सारणी: 06	चित्र एवं ग्राफ: 00	स्रोत एवं संदर्भ: 12
	मुख्य शब्द: सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश, एनपीए, कृषि ऋण, एससीएआरडीबी, वसूली दर।		

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, कृषि क्षेत्र वर्ष 2024–25 में जीएसडीपी में 24.9 प्रतिशत योगदान के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साथ ही, वर्ष 2024–25 में 737.4 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन के साथ देश का अग्रणी राज्य होने के कारण, यह प्रदेश व देश की विशाल जनसंख्या का भरण-पोषण करने के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है (आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26)। वर्तमान समय में भी प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका और रोजगार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था की विशिष्टता इसकी जोत संरचना में है, 2010–11 के आंकड़ों के अनुसार, कुल परिचालन जोत में सीमांत (79.5 प्रतिशत) और लघु किसानों (13 प्रतिशत) की संयुक्त हिस्सेदारी लगभग 92.5 प्रतिशत है। यह जोत संरचना स्पष्ट करती है कि राज्य की कृषि व्यवस्था मुख्य रूप से छोटे किसानों पर आधारित है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पता चलता है कि इन लघु और सीमांत किसानों के सामने एक मुख्य समस्या पूंजी की अनुपलब्धता रही है। स्वतंत्रता पूर्व और उसके बाद भी एक लंबे समय तक भारतीय किसान ऋण के लिए मुख्य रूप से साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहे हैं, जो इन किसानों से दिये गए ऋण पर ऊँची ब्याज दर

वसूलते थे, जिससे एक बार ऋण लेने के बाद चुका न पाने के कारण अधिकांश किसान 'कर्ज के जाल' में फंस जाते थे। हालाँकि, स्वतन्त्रता के बाद सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाए गए, लेकिन वाणिज्यिक बैंक अपनी "हाई स्ट्रीट" प्रकृति और कठोर मानकों के कारण छोटे किसानों तक पहुँचने में सफल नहीं हो सके। वाणिज्यिक बैंकों के इस ऐतिहासिक पूर्वाग्रह ने ग्रामीण वित्तीय समावेशन में एक बड़ा अंतर पैदा किया है।

इस शून्यता को भरने में सहकारी बैंक ग्रामीण ऋण प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में उभरे हैं। इन्हें भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की 'जीवन रेखा' माना जाता है क्योंकि इनका नेटवर्क जमीनी स्तर तक फैला हुआ है। सेवा के सिद्धांत पर आधारित ये बैंक छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों को साहूकारों के शोषण से बचाकर कम ब्याज दर पर समय पर ऋण उपलब्ध कराकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इस शोध पत्र में उत्तर प्रदेश के राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य और परिचालन दक्षता का अध्ययन किया जाएगा है।

1.1. भारत में कृषि ऋण प्रवाह में सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी: भारतीय कृषि ऋण प्रणाली में सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी में ऐतिहासिक रूप से भारी गिरावट दर्ज की गई है। 1970 के दशक में जहाँ कुल कृषि ऋण वितरण में सहकारी बैंकों का योगदान 80 प्रतिशत से अधिक था, वहीं हाल के वर्षों में यह घटकर 20 प्रतिशत से भी नीचे आ गया है। इस संरचनात्मक गिरावट के मुख्य कारणों में इन बैंकों की कमजोर वित्तीय स्थिति, सीमित पूंजी आधार, कुप्रबंधन और वाणिज्यिक बैंकों से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी पिछड़ापन, उच्च गैर-निष्पादित संपत्तियाँ और अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप भी इस पतन के अन्य प्रमुख कारक रहे हैं।

सारणी-1: भारत में कृषि ऋण प्रवाह में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और व्यवसायिक बैंकों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)			
वर्ष	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	व्यवसायिक बैंक
2012-2013	18	11	-
2013-2014	17	12	-
2014-2015	16.4	12.1	71.5
2015-2016	16.7	13	70.2
2016-2017	13.4	11.6	75
2017-2018	12.9	12.1	74.9
2018-2019	12.1	11.9	76
2019-2020	11.3	11.9	76.8
2020-2021	12.1	12.1	75.8
2021-2022	13.1	11	75.9
2022-2023	11	11.2	77.8
2023-2024	9.5	11.1	79.4
2024-2025	9	10.8	80.2

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

प्रस्तुत आंकड़ों का विश्लेषण भारतीय कृषि ऋण बाजार में हुए संरचनात्मक बदलाव को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। तालिका यह दर्शाती है कि सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी में निरंतर और तीव्र गिरावट आई है। वर्ष 2012-13 में जहाँ सहकारी बैंकों का योगदान 18 प्रतिशत था, वह वर्ष 2024-25 में घटकर मात्र 9 प्रतिशत रह गया है। यह 50 प्रतिशत की सीधी गिरावट सहकारी ढाँचे के अस्तित्व पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है। इसके विपरीत, व्यवसायिक बैंकों ने अपनी स्थिति को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया है। 2014-15 में उनकी हिस्सेदारी 71.5 प्रतिशत थी, जो 2024-25 में बढ़कर 80.2 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गई है। यह वृद्धि उनकी बेहतर तकनीक, व्यापक नेटवर्क और आक्रामक ऋण वितरण का परिणाम है। वहीं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थिति लगभग स्थिर है, जो पिछले एक दशक से 11-12 प्रतिशत के बीच ही सिमटे हुए हैं।

1.2. उत्तर प्रदेश में सहकारी साख का ढाँचा: उत्तर प्रदेश में अल्पकालिक ऋण के लिए एक सुदृढ़ संघीय त्रि-स्तरीय (3-Tier) ढाँचा कार्यरत है:

1.2.1. शीर्ष स्तर (State Level): उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, जो राज्य की सर्वोच्च वित्तीय संस्था है।

1.2.2. जिला स्तर (District Level): जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जो मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में ये बैंक प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में अपनी शाखाओं के माध्यम से सक्रिय हैं।

1.2.3. ग्राम स्तर (Village Level): प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस), जो सीधे किसानों से जुड़ी हैं और ऋण प्रणाली की आधारशिला हैं। विश्व बैंक और एनसीईआर के अनुसार, भारत में लगभग 30 प्रतिशत माइक्रो क्रेडिट इन्हीं पैक्स के माध्यम से वितरित किया जाता है।

1.3. समस्या का कथन: पिछले कुछ दशकों में, विशेषकर 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, भारतीय कृषि ऋण परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन आया है। यदि हम सहकारी बैंकों के दृष्टिकोण से देखें तो पता चलता है कि, जहाँ कुल कृषि ऋण में सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय हिस्सेदारी 2012-13 में 18 प्रतिशत थी वहीं 2024-25 में घटकर मात्र 9 प्रतिशत रह गई है। उत्तर प्रदेश में यह समस्या और भी जटिल है, जहाँ एक ओर राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) लाभ के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर दीर्घकालिक ऋण संरचना (एससीएआरडीबी) 76.2 प्रतिशत जैसे अत्यधिक उच्च एनपीए और 27.7 प्रतिशत की निम्न वसूली दर के कारण अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। ऋण अनुशासन में कमी, बढ़ता राजनीतिक हस्तक्षेप और वाणिज्यिक बैंकों से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा ने सहकारी बैंकिंग की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

1.4. शोध के उद्देश्य: प्रस्तुत शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति और उनकी लाभप्रदता की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना।
2. कृषि ऋण प्रवाह में सहकारी बैंकों की घटती हिस्सेदारी के कारणों की पड़ताल करना।
3. राज्य में एनपीए और ऋण वसूली के तुलनात्मक स्तर का मूल्यांकन करना।
4. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के डिजिटल रूपांतरण और तकनीकी उन्नयन की वर्तमान प्रगति का अध्ययन करना।

2. शोध प्रविधि: प्रस्तुत अध्ययन मुख्य रूप से द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़ों का संकलन भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, नापसकॉब की वार्षिक रिपोर्टों और लोकसभा के अभिलेखों से किया गया है। अध्ययन की अवधि मुख्य रूप से 2010 से 2025 तक की है, जिससे दीर्घकालिक प्रवृत्तियों और मौजूदा बदलावों का सटीक विश्लेषण किया जा सके। आंकड़ों की व्याख्या के लिए सांख्यिकीय विधियों और तुलनात्मक विश्लेषण का प्रयोग किया गया है।

3. डेटा विश्लेषण और व्याख्या:

3.1. उत्तर प्रदेश में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन: भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2017 से 2024 के मध्य उत्तर प्रदेश में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) की वित्तीय स्थिति में उच्चावचन और संरचनात्मक अस्थिरता की स्थिति परिलक्षित होती है। नीचे दी गई तालिका उत्तर प्रदेश और अखिल भारतीय स्तर पर एनपीए और वसूली दर की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाती है:

वर्ष (मार्च अंत)	उत्तर प्रदेश (NPA %)	भारत का औसत (NPA %)	उत्तर प्रदेश (Recovery %)	भारत (Recovery %)
2017	39.6	23.6	30.5	48.4
2018	44.1	25.0	25.3	46.1
2019	38.4	26.5	27.1	43.1
2020	72.1	33.0	25.5	47.1
2021	83.7	33.1	29.1	40.8
2022	80.2	36.1	29.1	42.8
2023	81.9	36.5	29.1	44.8
2024	76.2	38.3	27.7	40.8

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक के प्रकाशन एवं रिपोर्ट्स।

उपर्युक्त तालिका-2 के आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश के एससीएआरडीबी के एनपीए में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। एनपीए की दर यह दर वर्ष 2017 में 39.6 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2021 में तेजी से बढ़कर 83.7 प्रतिशत के चिंताजनक स्तर पर पहुँच गया। यद्यपि 2024 (अनंतिम आंकड़ों) में इसमें मामूली गिरावट आई और यह 76.2 प्रतिशत दर्ज किया गया, फिर भी यह अत्यधिक उच्च बना हुआ है। इसके विपरीत, अखिल भारतीय स्तर पर एनपीए अनुपात तुलनात्मक रूप से मध्यम रहा, जो 2017 में 23.6 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 38.3 प्रतिशत तक पहुँचा। वसूली निष्पादन के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश की स्थिति राष्ट्रीय मानकों की तुलना में लगातार दयनीय बनी हुई है। समीक्षाधीन अवधि (2017-2024) के दौरान राज्य में वसूली दर 25 से 30 प्रतिशत के बीच ही सीमित रही, जबकि

राष्ट्रीय औसत 40 से 48 प्रतिशत के बीच रहा है। उच्च एनपीए और निम्न वसूली दर के बीच का यह विलोम संबंध (Inverse Relationship) राज्य में 'साख अनुशासन' (Credit Discipline) को लागू करने में विफलता को प्रदर्शित करता है। यद्यपि 2021–2023 के दौरान कुछ सीमांत सुधार देखे गए, किंतु वसूली दक्षता अभी भी राष्ट्रीय बेंचमार्क तक पहुँचने में असमर्थ रही है, जो संस्था की वित्तीय स्थिरता के लिए एक प्रमुख बाधा है।

3.2. शाखा नेटवर्क और लाभप्रदता: उत्तर प्रदेश में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) एक 'एकात्मक संरचना' का अनुसरण करते हैं। तालिका-3 के आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि समीक्षाधीन अवधि (2018–2024) के दौरान बैंक की शाखाओं की संख्या 323 पर स्थिर बनी रही। शाखा विस्तार में यह स्थिरता (Stagnation) बैंक की संस्थागत पहुंच और ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने में सीमित वृद्धि को इंगित करती है।

सारणी-3: उत्तर प्रदेश एससीएआरडीबी का शाखा नेटवर्क और लाभप्रदता (लाख रु. में)			
वर्ष (मार्च अंत)	शाखाओं की संख्या	लाभ (+) / हानि (-) (लाख रु. में)	टिप्पणी
2018	323	+192	सीमांत लाभ
2019	323	-8,451	भारी घाटा
2020	323	+9,770	तीव्र वापसी
2021	323	+2,323	लाभ में गिरावट
2024 (अंतिम)	323	+9,831	स्थिर लाभप्रदता
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक			

वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण लाभप्रदता में भारी अस्थिरता और विरोधाभास को उजागर करता है। जहाँ 2019 में 8,451 लाख रुपये का घाटा था, वहीं 2024 में लाभ 9,831 लाख रुपये पहुँच गया। हालांकि, 76.2 प्रतिशत के उच्च एनपीए के साथ यह लाभ असंगत है, जो वास्तविक परिचालन मजबूती के बजाय सरकारी सहायता या लेखांकन समायोजन जैसे कृत्रिम सुधारों का संकेत देता है।

3.3. उत्तर प्रदेश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण: प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ सहकारी ढांचे की आधारशिला हैं। नाबार्ड और लोकसभा के अभिलेखों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण उत्तर प्रदेश में पैक्स के कंप्यूटरीकरण परियोजना की प्रगति और वित्तीय आवंटन की स्थिति को दर्शाता है।

सारणी-4 : उत्तर प्रदेश में पैक्स कंप्यूटरीकरण हेतु निधियों का आवंटन एवं उपयोग (करोड़ रु. में)			
वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि	जारी राशि	उपयोग राशि
2022-23	11.28	11.28	0.00
2023-24	43.87	42.30	24.10
2024-25	50.88	0.00	-
स्रोत: लोकसभा अतारंकित पत्र संख्या 1181 (दिनांक 03.12.2024) एवं पत्र संख्या 1487 (दिनांक 09.12.2025), भारत सरकार।			

उत्तर प्रदेश में पैक्स के कंप्यूटरीकरण हेतु आंकड़ों का विश्लेषण प्रारंभिक जड़ता और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों को उजागर करता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में शत-प्रतिशत आवंटन के बावजूद शून्य उपयोग प्रशासनिक शिथिलता को दर्शाता है, हालांकि 2023–24 में 57 प्रतिशत निधि के उपयोग ने सुधार के संकेत दिए हैं। इसके बावजूद, 2024–25 में उच्च आवंटन के बाद भी फंड जारी होने में देरी प्रशासनिक बाधाओं और शसीमित कार्यान्वयन क्षमता की पुष्टि करती है। निष्कर्षतः, पैक्स का डिजिटल रूपांतरण पारदर्शिता और वसूली प्रदर्शन के लिए अनिवार्य है, किंतु निधियों का विलंबित उपयोग इस सुधार प्रक्रिया को बाधित कर रहा है, जिसके लिए तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक है।

3.4. उत्तर प्रदेश में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति: अल्पकालिक सहकारी साख संरचना के अंतर्गत जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 के नवीनतम अंतिम आंकड़ों का विश्लेषण उत्तर प्रदेश में इन बैंकों के संतोषजनक प्रदर्शन और वित्तीय स्थिरता को प्रदर्शित करता है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के आंकड़े उत्तर प्रदेश के सभी 50 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में पूर्ण लाभप्रदता और 18,564 लाख रु. का संचयी लाभ दर्शाते हैं, जो कुशल परिचालन प्रबंधन का परिचायक है। 5.8 प्रतिशत का निम्न एनपीए और 81.2 प्रतिशत की उच्च वसूली दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन की पुष्टि करती है, जिससे बैंकों का नकदी प्रवाह और ऋण पुनर्चक्रण मजबूत हुआ है। तुलनात्मक रूप से, ये अल्पकालिक ऋण संस्थान राज्य-स्तरीय

दीर्घकालिक संस्थानों (एससीएआरडीबी) की अपेक्षा अधिक वित्तीय अनुशासन और बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं। निष्कर्षतः, जिला स्तर पर प्रभावी ऋण मूल्यांकन ने इन बैंकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है।

सारणी-5: उत्तर प्रदेश बनाम भारत: डीसीसीबी के प्रमुख वित्तीय संकेतक (2024-25)					
क्षेत्र / मानक	डीसीसीबी की संख्या	लाभार्जन करने वाले बैंकों की संख्या	कुल लाभ (लाख रु.)	एनपीए अनुपात (%)	वसूली दर (%)
उत्तर प्रदेश	50	50	18,564	5.8%	81.2%
अखिल भारत	351	301	3,66,986	8.7%	76.4%
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक, 2024-25।					

3.5. कृषि ऋण वसूली और मांग का विश्लेषण: नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड (नाफ्सकॉब) से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण उत्तर प्रदेश में सहकारी ऋणों की प्रकृति और उनकी केंद्रित प्रवृत्तियों को उजागर करता है।

सारणी-6: उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंकों की ऋण वसूली का वर्गीकरण (लाख रु.)			
ऋण श्रेणी	कृषि वसूली	गैर-कृषि वसूली	कुल वसूली
अल्पकालिक	4,62,006	29,640	4,91,646
मध्यम-कालिक	0	0	0
अन्य	-	-	498
कुल योग	4,62,006	29,640	4,92,144
स्रोत: नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड (नाफ्सकॉब), 2023-24।			

उत्तर प्रदेश की सहकारी ऋण संरचना के विश्लेषण से स्पष्ट है कि यहाँ ऋण वसूली मुख्य रूप से अल्पकालिक कृषि ऋणों तक सीमित है, जो कुल वसूली का लगभग 94 प्रतिशत (4,62,006 लाख रुपये) है। गैर-कृषि वसूली का अत्यंत न्यून होना और मध्यम-कालिक ऋणों की वसूली का शून्य होना ग्रामीण साख विविधीकरण के अभाव को दर्शाता है। ऋण की मांग और वसूली का यह असंतुलित स्वरूप इंगित करता है कि ये बैंक केवल मौसमी फसल ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने तक सिमट गए हैं। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में श्रृंखला निर्माण और श्रृंखला विविधीकरण को बाधित करती है। सतत विकास हेतु इन बैंकों को पारंपरिक फसल ऋण प्रदाता की छवि से बाहर निकलकर एक बहुआयामी वित्तीय संस्थान के रूप में विकसित होना अनिवार्य है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : प्रस्तुत शोध पत्र का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) वर्तमान में एक गंभीर वित्तीय संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। प्रमुख वित्तीय संकेतकों का अध्ययन करने पर प्राप्त निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि जहाँ शीर्ष स्तर पर शराज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) लाभप्रदता और एनपीए प्रबंधन में सफल रहा है, वहीं दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने वाले एससीएआरडीबी संरचनात्मक विफलता के कगार पर हैं। विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश के एससीएआरडीबी में एनपीए का स्तर (76.2 प्रतिशत) राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुना है, जो ऋण मूल्यांकन और परिसंपत्ति प्रबंधन की प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। इसके अतिरिक्त, 27.7 प्रतिशत की अत्यंत न्यून वसूली दर यह सिद्ध करती है कि राज्य में दीर्घकालिक कृषि निवेश हेतु ऋण अनुशासन का अभाव है। यद्यपि 2018 के बाद लाभप्रदता के आंकड़ों में कृत्रिम सुधार देखा गया है, किंतु उच्च एनपीए के साथ इसकी असंगतता यह संकेत देती है कि यह सुधार वास्तविक परिचालन दक्षता के बजाय सरकारी पुनर्पूजीकरण और बजटीय सहायता का परिणाम अधिक है।

उत्तर प्रदेश में कृषि ऋण के प्रवाह में सहकारी बैंकों की घटती बाजार हिस्सेदारी (जो राष्ट्रीय स्तर पर 18 प्रतिशत से गिरकर 9 प्रतिशत रह गई है) यह चेतावनी देती है कि इन संस्थानों को तत्काल तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है। पैक्स (पीएसीएस) के कंप्यूटरीकरण में देखी गई श्रारंभिक जड़ता और निधियों का विलंबित उपयोग डिजिटल रूपांतरण की गति को बाधित कर रहा है। यदि इन बैंकों को ग्रामीण उत्तर प्रदेश की शजीवन रेखा के रूप में पुनर्जीवित करना है, तो अल्पकालिक जिला सहकारी बैंकों के सफल मॉडल को अपनाते हुए दीर्घकालिक ऋण तंत्र में भी कठोर वसूली प्रक्रिया, तकनीकी पारदर्शिता और व्यावसायिक प्रबंधन को अनिवार्य रूप से

लागू करना होगा। बिना इन मूलभूत परिवर्तनों के, वाणिज्यिक बैंकों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच सहकारी साख संरचना की प्रासंगिकता बनाए रखना एक कठिन चुनौती होगी।

स्रोत एवं संदर्भ:

1. Agarwal, S. (2019). Role of cooperative bank in rural credit. *Remarking: An Analysation*, 3(11), E-4–E-9.
2. Chaudhari, V. M., & Farmer, M. (2022). An empirical study of structure and performance of state co-operative agriculture and rural development banks and affiliated primary cooperative agriculture and rural development banks in India. *Gujarat Journal of Extension Education*, 33(1), 41–52. <https://doi.org/10.56572/gjoe.2022.33.1.0010>
3. Kanchan. (2016). Role of cooperative banks in agricultural finance: The case study of Punjab. *International Education & Research Journal*, 2(11).
4. Mishra, A. (2019). Banking reform and agriculture financing through banks in Uttar Pradesh. *Contemporary Social Sciences*, 28(1), 192–205.
5. Prasad, R. K., Rizvi, A. Z., Srivastava, N. K., & Kumar, S. (2020). Promoting business through co-operative marketing: An empirical study in Uttar Pradesh. *International Journal of All Research Education and Scientific Methods (IJARESM)*, 8(12), 989–1008.
6. Rajesh, U., & Kalluraya, S. (2024). The role of credit co-operative institutions in agriculture: A review. *TIJER - International Research Journal*, 11(1), 280–286.
7. Sahni, M. (2019). Agriculture credit by cooperative bank in India: An analysis. *International Journal of Engineering Development and Research (IJEDR)*.
8. Singh, A. (2020). Role of cooperative banks in agricultural development. *International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology (IARJSET)*, 7(6), 45–49. <https://doi.org/10.17148/IARJSET.2020.7605>
9. Soni, A. K., & Saluja, H. P. S. (2012). Role of cooperative bank in agricultural credit: A study based on Chhattisgarh. *Abhinav National Monthly Refereed Journal of Research in Commerce & Management*, 1(10), 106–112.
10. The Uttar Pradesh Agricultural Credit Act, 1973.
11. Uma Devi, R., & Govt, S. R. K. (2012). The role of credit co-operatives in the agricultural development of Andhra Pradesh, India. *International Journal of Cooperative Studies*, 1(2), 55–64.
12. Zaidi, S., & Tiwari, M. (2018). Agricultural credit issues and its growth in Uttar Pradesh. *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)*.

=====

आलेख उद्धरित करें :	चौरसिया, वीरेन्द्र प्रताप (2026)। उत्तर प्रदेश में सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषणात्मक अध्ययन। <i>बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर)</i> , वॉल्यूम-2, अंक-2, अप्रैल-जून, 2026, पृष्ठ 53–58। https://doi.org/10.5281/zenodo.21790001
---------------------	--